the best heart surgery arrangement is in the Vellore hospital where the minimum amount of Rs. 15,000 is required for the operation of a heart patient? I know many cases where patients have applied to the Central Government as well as to the state Government but in very few cases they are getting any help either in money or in any way, recommending or arranging with the Vellore hospital, to see that the poor patients get the facility of heart surgery without any cost. Would the hon. Minister do something in this regard?

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि यह सदन कृपा करके हमारे पास इतनी निधि रखवा दे कि हमें किसी भी हार्ट पेशन्ट, किडनी पेशन्ट और कैंसर के पेशन्ट को वापस करने की आवश्यकता न पड़े और हम उन सब की चिकित्सा मुफ्त करा सकें। मैं चाहता हूं कि भगवान् वह दिन जल्दी लायें, जबकि हमारे पास इतने फंड्ज हो जायें। यह सदन स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना रुपया दिलवा दे—हमारा पैसा बढ़वा दे।

SHRI B. RACHAIAH: The hon. Minister of Health seems to be having more experience with regard to the diseases of heart and hyper-tension. He has suggested some Ayurvedic medicine which costs very much less. Would he be pleased to write a book prescribing Ayurvedic medicines to the patients who are suffering from heart disease, hyper-tension and low blood pressure? Would he undertake that job?

श्री राज नारायण : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने एक व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछा है। आयुर्वेदिक पद्धति, एलोपैथिक पद्धति, सारी पद्धतियों का विचार कर के मैं निवेदन कर रहा हूं और अगर आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जानना हो तो उस में कुछ विशेष रुचि लेकर पढ़ने की कृपा करें। अभी दो दिन का एक सेमिनार हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट में कि किस तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से ये जो भीतरी रोग हैं उन को दूर किया जाय और लोगों ने यह पाया कि आयुर्वेदिक पद्धति सब से अच्छी पद्धति है। इसलिए आयुर्वेदिक पद्धति को भी लोग इस्तेमाल करें हृदय रोग को दूर करने के लिए तो यह एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति को भी कुछ लोग महंगा करते जा रहे हैं, जैसे मोती भस्म, स्वर्ण-भस्म और हीरा-भस्म, जो हार्ट के काम में आते हैं, ये इतने महंगे हो गए हैं कि उस के लिए भी काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि साइंस सिस्टम कैसे हो, क्या हो, सब का क्या निरूपण हो, रोगों को दूर करने के लिए क्या उपकरण किया जाय, इस की व्यवस्था करने के लिए एक कमेटी हम ने बैठायी है। वह इस की जांच करेगी कि क्या-क्या किया जाय। इसीलिए हम ने अपने इंडिजिनस सिस्टम के चार विभाग कर दिए हैं और सब विभाग अलग-अलग ढंग से इस पर अपनी राय देंगे।

Private Practice by Doctors

*1072. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to frame any rule for banning private practice by Government medical doctors; and

(b) if so, the details thereof?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सरकार का विचार सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोकने के लिए कोई भी नियम बनाने का नहीं है क्यों कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों को विचार करना है। 29 से 31 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के चौथे संयुक्त सम्मेलन ने सर्व सम्मति से यह सिफारिश की है कि सरकारी डाक्टरों तथा मेडिकल कालेजों में कार्य कर रहे डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाये और उन्हें अतिपूरक प्रेक्टिस-बन्दी भत्ता दिया जाए। यह सिफारिश आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। भारत सरकार के अधीन डाक्टरों के प्राइवेट प्रेक्टिस करने पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

श्री गण नाथ प्रधान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या कोई सिफारिश इस सम्बन्ध में उनको मिली है? यदि मिली है तो क्या उन्होंने सेंटर की ओर से उस के लिए गाइडलाइन्स बनाने के लिए कुछ काम किया है? यह गाइडलाइन्स वह कब तक बनाएंगे और ये डाक्टर लोग गांवों में जा कर गांव वालों के बीच में कुछ दिन काम करें, यह उन के लिए कम्पल्सरी करने के लिए कोई ला वह कब तक बनाने जा रहे हैं?

श्री राजनारायण : सम्मानित सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केन्द्र का विषय नहीं है। राज्य सरकारें इस पर समुचित कानून बना सकती हैं।

हमने दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की जो बैठक की थी उस बैठक में निर्णय ले लिया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में हम कानून नहीं बना सकते । इसलिए राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही करने के लिए सिफारिश भेज दी गई है क्योंकि हमारे पास वह शक्ति नहीं है ।

श्री गजानन प्रधान : अध्यक्ष महोदय, देहातों में जाकर चिकित्सा कार्य डाक्टरों के लिए कम्पलसरी करने के लिए अभी तक केन्द्र ने कुछ नहीं किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में गाइडलाइन्स राज्यों को देने की कृपा करेगी ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य का सुझाव अच्छा है । मैं समझता था कि एक न एक दिन इस तरह का प्रश्न सदन में उठेगा । (व्यवधान) सम्मानित सदस्य जरा सुन लें । हमारी इच्छा है मगर हमारी सभी इच्छायें कार्य रूप में परिणत हो जायें, यह आवश्यक नहीं है, हम तो चाहेंगे कि परिणत हो जायें । राज्य सरकारों के पास यह शक्ति है, हम उनसे कहते हैं कि हमने सेन्टर के लिए रोक लगा दी है, आप राज्यों के लिए भी रोक लगायें, आप भी इसका अनुकरण करें । एक बात मैं इस सम्मानित सदन की जानकारी के लिए बतला दूं कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बिठा रखी है डा० संकरन की अध्यक्षता में जोकि डायरेक्टर जनरल हैं । इसमें इंडियन मेडिकल कौंसिल के चेयरमैन हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के डा० रामलिंगम् स्वामी हैं । ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स की यह कमेटी है । हम चाहते हैं कि यह कमेटी इन सारे पहलुओं पर विचार करे कि इन्टर्नशिप कितनी हो, हाउस जाब कब मिले, इन्टर्नशिप और हाउस जाब को क्या एक में मिला दिया जाये, पांच साल का कोर्स तीन साल कर दिया जाये या एक साल बढ़ा कर चार साल कर दिया जाये या प्रतिबंधित कर दिया जाये कि दो साल देहातों में काम करने के बाद तब सर्टिफिकेट दिया जाये ।

MR. SPEAKER: You have gone much beyond the question.

SHRI RAJ NARAIN: He wanted to know about this point.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: In case Government propose to ban private practice by Government doctors, will the same formula apply to the teachers, including postgraduate teachers, in Ayurvedic Colleges where N. P. allowance is not given? There are many problems in respect of fixation of salary. If proper salary, in tune with the rising cost of living, is given, the doctors would not be lured to going in for private practice. I particularly draw your attention to the long-standing complaints of fixation of salaries, N. P. allowance, etc., of the teachers of the Ayurvedic University at Jamnagar, which is the first of its kind in the country ..

MR. SPEAKER: We are on a general question.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: I want to know whether the same formula will be applicable to the teachers of Ayurvedic Colleges.

श्री राज नारायण : एक प्रकार से यह प्रश्न पहले ही आ चुका है । आपके द्वारा मैंने सदन से निवेदन किया था कि इन सारे मसलों पर विचार करने के लिए एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी की बैठक के लिए 29 तारीख भी तय हो गयी है । डा० संकरन जब मुझे जेनेवा में मिले थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कमेटी की कब बुलायेंगे तो उन्होंने कहा कि 29 तारीख फिक्स करके आया हूं । तो उस कमेटी में यह सारी बातें तय होंगी । आप जानते हैं हमने सौ रुपया इन्टर्नीज का बढ़ा दिया और मैं उड़ीसा गया था तो उन्होंने कहा कि हम दो सौ देते थे आपने सौ क्यों बढ़ा दिया इस तरह से हमारी तो मुश्किल हो गई । (व्यवधान) इस तरह से एलोपैथी हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, सभी के लिए विचार है ।

जिलों और सब-डिवीजनों और भागलपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

*1073. डा० इलजी सिंह : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड क्या हैं ;

(ख) जिला और सब-डिवीजन मुख्यालयों में कितने स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गए हैं ;

(ग) क्या बिहार में भागलपुर में कोई स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं है जो केवल जिला ही नहीं बल्कि कमिश्नरी का मुख्यालय है और विश्वविद्यालय भी है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) वहां पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई यह रही है कि उपयुक्त आटोमेटिक टेलीफोन